**Title:** Regarding delay in passing of the Reservation Act for protecting the interests of the employees and students belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes community and withdrawal of the circulars passed by the DoPT relating to the matter.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Mr. Deputy-Speaker, thank you very much for giving me an opportunity. Through you, I want to bring to the notice of the hon. Minister present here that the entire country is aware about the loss done to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribe employees and students on account of the five nasty circulars issued by the DoPT from January, 1997 to August, 1998. The hon. Prime Minister has given assurances more than four times in this regard. ...(*Interruptions*) Yesterday also, the hon. Prime Minister referred to one of the amendments passed in this august House. I am extremely sorry that in spite of the entire House voting for the said amendment, it is not implemented in the field and the assurances of passing legislation to undo the remaining four DoPT circulars is yet awaited by the lakhs and lakhs of employees and students all over the country. I want that the Government should bring an appropriate legislation in the form of the Reservation Act, which is the only solution, so that the courts are not allowed to intervene as far as the Fundamental Rights and the Constitutional Rights of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are concerned.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramdas Athawale wants to raise the same matter. So I thought I should give him a last chance.

**श्री रामदास आठ्वले (पंढरपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, 22 दिसम्बर 1999 को प्रधान मंत्री जी ने अनुसूचित जाति/ जनजाति रिज़र्वेशन एक्ट बनाने के लिए हमें आश्वासित किया था। â€¦( व्यवधान) प्रधान मंत्री जी ने 22 दिसम्बर, 1999 को इसी हाउस में अनुसूचित जाति/जनजाति के रिज़र्वेशन को प्रोटेक्शन देने के लिए नया रिज़र्वेशने एक्ट बनाने के लिए आश्वासित किया था। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में क्या करने वाली है और जो पांच आफिस मेमोरेंडम निकले थे, उनमें से जो आफिस मेमोरेंडम बाकी हैं, उनको विदड्रा करने के बारे में भी आपकी सरकार ने आश्वासित किया था। इस बारे में आप कुछ आश्वासन दीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब आप शांति से बैठिये।

**श्री प्रमोद महाजन :** उपाध्यक्ष महोदय, दोनों सम्माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विाय उठाया है। सदन यह जानता है कि 1997 में इस प्रकार के पांच परिपत्रक निकले थे जिसके कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों के सामने जो समस्या आ रही थी, उसके लिए एक संविधान संशोधन भी इस सदन ने पारित किया है। दूसरा संविधान संशोधन कल राज्य सभा में और उसके अगले हफ्ते लोक सभा में पारित किया जायेगा। लेकिन बहुत सारे सदस्यों की शिकायत आई है कि जमीन पर इसके कार्यान्वयन में कोई समस्या खड़ी हो रही है। मैं निश्चित रूप से प्रधान मंत्री और कार्मिक मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्ति करूंगा।